www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

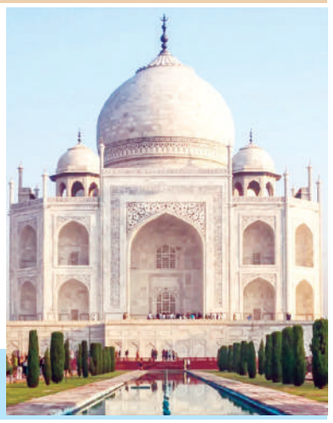

2 भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी

3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के...

4 ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक...

वर्ष: 10 | अंक: 104 | दिल्ली, शुक्रवार, 6 फरवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया तो सदन नहीं चलेगा-जयराम रमेश

नई दिल्ली (एजेन्सी)। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने गुरुवार को चेतावनी दी कि अगर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को 2020 में चीन के साथ हुए गतिरोध पर संसद में अपनी बात रखने की अनुमति नहीं दी गई तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम रह जाएगी। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि संसद में केवल एक ही मुद्दा है जो विपक्ष को परेशान कर रहा है, और वह यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने से रोका गया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने भी यही मुद्दा उठाया। राज्यसभा में विपक्षी सांसद भी आज इसी मुद्दे पर सदन से बाहर चले गए। रमेश ने आगे कहा कि सभी विपक्षी दल इस बात पर एकमत हैं कि अगर लोकसभा सांसद को बोलने नहीं दिया गया, तो सदन के चलने की संभावना बहुत कम है। कांग्रेस ने संसद में कई मुद्दे उठाए हैं, जिनमें से एक प्रमुख मुद्दा पूर्वी लद्दाख में 2020 के चीन गतिरोध पर एमएम नरवणे के अप्रकाशित संस्मरण से जुड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा सांसद राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे (सेवानिवृत्त) के उद्धरण देने से कई बार "रोका" गया। भाजपा नेताओं ने बचाव में कहा कि यह सदन के नियमों का उल्लंघन है और इससे सशस्त्र बलों का मनोबल गिरने का खतरा है।

बिहार में अब नहीं बजेंगे डबल मीनिंग वाले गाने

बिहार (एजेन्सी)। बिहार के उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील और आपत्तिजनक गीतों को बजाने के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के अनुसार, बसों, ट्रकों, ऑटो-रिक्शा या सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील या आपत्तिजनक गीत बजाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, चाहे वह भोजपुरी, मगही, मैथिली या किसी अन्य भाषा में हो। सम्राट चौधरी ने अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गानों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में विशेष अभियान चलाने और ऐसे मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कॉ सार्वजनिक स्थानों, समारोहों और वाहनों में इस तरह के गानों का प्रसारण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सस्ते दोहरे अर्थ वाले और अश्लील गाने समाज के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं।

'किसान हित सर्वोपरि', मुख्य अनाज, मिलेट्स, फल और डेयरी उत्पादों पर कोई खतरा नहीं-चौहान

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। भारत-यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे भ्रामक आरोपों के बीच केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट किया है कि इस समझौते में भारतीय कृषि, विशेषकर कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह डील प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में डिप्लोमेसी, डेवलपमेंट और डिग्निटी का नया उदाहरण है और प्रधानमंत्री जी ने शुरू से साफ कर दिया था कि किसान हित सर्वोपरि हैं।

दिल्ली में मीडिया से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे मुख्य अनाज, फल, प्रमुख फसलें, मिलेट्स और डेयरी उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित हैं और भारतीय कृषि या डेयरी पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित पूरी तरह संरक्षित हैं और इस समझौते से उल्टा भारत के किसानों को नए अवसर मिलेंगे।

इस आशंका पर कि देश की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर है और छोटे किसानों पर असर पड़ सकता है, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि कोई बड़ी चीज भारत के बाजार में अचानक नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि हमारी सभी मुख्य फसलें, मुख्य अनाज, फल और डेयरी उत्पाद सुरक्षित हैं और किसी भी ऐसे क्षेत्र के लिए बाजार नहीं खोला गया है, जो भारतीय किसानों के लिए नुकसानदेह हो सके।

टैरिफ घटने से चावल, मसाले और टेक्सटाइल निर्यात को मिलेगा बल, कपास किसानों की आय बढ़ेगी-शिवराज सिंह

यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी के उस ट्वीट से पैदा संशय पर, जिसमें अमेरिकी फार्म प्रोडक्ट्स के ज्यादा भारत आने की बात कही गई थी, श्री चौहान ने कहा कि वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल ने संसद में पूरे तथ्य स्पष्ट कर दिए हैं और वे स्वयं भी दोहरा रहे हैं कि छोटे और बड़े, सभी भारतीय किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और मुख्य कृषि उत्पादों के लिए बाजार इस प्रकार नहीं खोला गया है कि किसानों पर दबाव बने। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि भारत पहले से ही अमेरिका सहित विभिन्न देशों को चावल का बड़ा निर्यातक है और हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 63,000 करोड़ रुपये के चावल का निर्यात किया गया था। उन्होंने कहा कि टैरिफ कम होने से हमारे चावल, मसालों और टेक्सटाइल के निर्यात को बल मिलेगा और जब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इसका सीधा लाभ कपास उगाने वाले हमारे किसानों को होगा।

श्री चौहान ने कहा कि यह समझौता समग्र रूप से भारत के किसानों के हित में है और विपक्ष द्वारा भ्रम फैलाने के बावजूद तथ्य यही हैं कि किसान हित सुरक्षित हैं और निर्यात के नए अवसर खुल रहे हैं।

जब यह सवाल उठा कि विपक्ष कह रहा है कि अगर ट्रेड डील कर रहे हैं तो सरकार आकर फाइन प्रिंट को संसद और देश के सामने समझाए, तो कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने दोहराया कि डील की सारी डिटेल्स समय पर सामने आएंगी, लेकिन उसका मूल साफ है झ किसानों के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं।

कृषि मंत्री ने चिंता जताई कि कृषि का क्षेत्र इतना बड़ा है कि किसी भी तरह की अफवाह से किसानों में अनावश्यक चिंता और बेचैनी पैदा हो सकती है, इसलिए सरकार की ओर से स्पष्ट आश्वासन देना जरूरी है। उन्होंने कहा, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, किसान अन्नदाता हैं, अन्नदाता मतलब जीवनदाता। उनके हित ही देश के हित हैं और वे हित सुरक्षित हैं।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भावुक शब्दों में कहा कि किसानों की सेवा सरकार के लिए भगवान की पूजा के समान है और मोदी सरकार हर कदम पर किसान के पक्ष में खड़ी रहेगी।

किसानों को अब 5 मिनट में ई-केसीसी से ऋण: सीएम योगी आदित्यनाथ

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस ने उत्तर प्रदेश में ऋण स्वीकृति की तस्वीर ही बदल दी है। अन्नदाता किसान जब पहले किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से ऋण लेने जाता था, तो 25 दिन से लेकर एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज वही किसान ई-केसीसी के माध्यम से मात्र पांच मिनट में ऋण सुविधा प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए जो हमारा कृषि ऋण 3 लाख करोड़ है, यह पहले की तुलना में 13 फीसदी बढ़ा है। यही सुशासन है और इसी दिशा में हमें और मजबूती से आगे बढ़ना होगा।

मुख्यमंत्री गुरुवार को लोकभवन में आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 के विमोचन के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज सरकार और अन्नदाता किसान मिलकर सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग खेती में कैसे किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से केंद्रीय बजट में एआई एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म की घोषणा की गई है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कई एफपीओ (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) को मंच पर सम्मानित भी किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संगोष्ठी में जो मॉडल प्रस्तुत किए गए, वे पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा हैं। दिव्यांगजनों द्वारा संचालित कसया मिल्क प्रोड्यूसर एफपीओ, जिसमें 1,005 सदस्य हैं, इसका जीवंत उदाहरण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में, जिन्हें पहले कमजोर माना जाता था, दिव्यांगजनों ने अपनी मेहनत और क्षमता से नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह आंखें खोलने वाला काम है और इसके लिए वे सभी अभिनंदन के पात्र हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया राज्य ऋण संगोष्ठी एवं राज्य फोकस पेपर 2026-27 का विमोचन

मुख्यमंत्री ने मथुरा की 750 महिलाओं वाली सरसों उत्पादन कंपनी का उल्लेख करते हुए कहा कि मैंने स्वयं उनकी प्रदर्शनी देखी है। किस तरह मस्टर्ड ऑयल को प्रोसेसिंग से जोड़कर महिलाओं ने बेहतर मुनाफा कमाया, यह पूरे प्रदेश के लिए सीख है। सरकार इस तरह के प्रयासों को हर स्तर पर सहयोग देगी। सीएम योगी ने कहा कि आज सहकारिता क्षेत्र भी बदल रहा है। सहकार से समृद्धि की ओर के विजन के तहत डिजिटलीकरण, ई-गवर्नेंस और पारदर्शी नीतियों से सहकारी संस्थाओं में सुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जो विश्व बैंक के साथ एग्री-टेक के क्षेत्र में काम कर रहा है।

कृषि, एमएसएमई, महिला, एग्री-टेक और युवा उद्यमिता आज सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की स्थिति को याद करते हुए कहा कि सहकारिता क्षेत्र में माफिया हावी था। रिजर्व बैंक ने 16 जिला सरकारी बैंकों को डिफाल्टर घोषित कर बंदी का आदेश कर दिया था। आज हमारी सरकार में इन्हीं 16 में से 15 बैंक प्रॉफिट में आ चुके हैं और 16वें को भी प्रॉफिट में लाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर में भी एक समय ऐसा था, जब उत्तर प्रदेश से बड़े पैमाने पर पलायन हो चुका था।

'भारत टैक्सी' की शुरूआत, ग्राहकों को मिलेगी बेहद सस्ती सवारी

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

नई दिल्ली। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देश के पहले सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच भारत टैक्सी की शुरूआत की। दो महीने के सफल पायलट परीक्षण के बाद शुरू की गई यह टैक्सी सेवा फिलहाल दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में शुरू की गई है।

इस मंच के उद्घाटन अवसर पर अमित शाह ने कहा, अगले तीन वर्षों में भारत टैक्सी सेवा को कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक देशभर में चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऑनलाइन टैक्सी सेवा मंच से होने वाला लाभ इससे जुड़े ड्राइवरों के साथ साझा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इस टैक्सी सेवा के तहत ग्राहक आवागमन के लिए कार के साथ तिपहिया और दोपहिया वाहनों की भी बुकिंग कर सकेंगे। फिलहाल देश के ऑनलाइन टैक्सी बाजार पर उबर, ओला और रैपिडो जैसी कुछ चुनिंदा कंपनियों का वर्चस्व है। हम आपको बता दें कि बहु-राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2002 के तहत पंजीकृत भारत टैक्सी मंच की स्थापना छह जून, 2025 को की गई थी। इस मंच पर न तो किसी कमीशन का प्रावधान है और न ही व्यस्त समय में किसी तरह की किराया बढ़ोतरी का प्रावधान होगा। इसमें मुनाफे का सीधा वितरण ड्राइवरों के बीच किया जाता है।

आठ प्रमुख सहकारी संगठनों के सहयोग से शुरू हुए इस मंच ने दो दिसंबर को दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में पायलट संचालन शुरू किया था। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, भारत टैक्सी दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सहकारिता-आधारित टैक्सी सेवा मंच और ड्राइवरों के स्वामित्व वाला सबसे बड़ा परिवहन मंच बनकर उभरा है। पायलट चरण के बाद से अब तक तीन लाख से अधिक ड्राइवर इस मंच से जुड़ चुके हैं, जबकि एक लाख से ज्यादा उपयोगकर्ताओं ने पंजीकरण कराया है। दिल्ली-एनसीआर और गुजरात में प्रतिदिन 10,000 से अधिक यात्राएं पूरी की जा रही हैं और अब तक करीब 10 करोड़ रुपये सीधे ड्राइवरों को वितरित किए जा चुके हैं। इस मंच से जुड़े ड्राइवरों को सारथी कहा जाता है। यह उनके लिए स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, सेवानिवृत्ति बचत और समर्पित सहायता प्रणाली जैसी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को भी प्राथमिकता देता है।

यह देश का पहला ऐसा मंच है जो सहकारी मालिकाना ढांचे पर आधारित है और जिसका मुख्य विचार है कि सारथी ही मालिक हो। इस योजना का लक्ष्य चालकों को अधिक कमाई, सामाजिक सुरक्षा और काम में सम्मान देना है, साथ ही यात्रियों को उचित और पारदर्शी किराये पर सवारी उपलब्ध कराना है।

भारत टैक्सी को ओला और उबर जैसे निजी मंचों के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सरकार के अनुसार इस मंच पर चालकों से कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा और अचानक बढ़ने वाले किराये यानी सर्ज प्राइसिंग का प्रावधान भी नहीं होगा।

किसानों को सशक्त बनाने किया जा रहा है तकनीक का प्रभावी उपयोग: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एसबी संवाददाता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों को सशक्त बनाने और कृषि व्यवस्था को आधुनिक स्वरूप देने के लिए तकनीक का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। एआई आधारित डिजिटल क्रॉप सर्वे और फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राज्य में ग्रामीण डेटा प्रणाली को एक नई दिशा प्रदान की गई है। उन्नत तकनीक, पारदर्शी डेटा प्रबंधन और केंद्र-राज्य समन्वय से यह पहल किसानों के हित में मजबूत डिजिटल आधार तैयार कर रही है। इससे किसानों को योजनाओं का वास्तविक लाभ सुनिश्चित होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से खेत पर उपस्थित होकर फसल की फोटो लेकर जानकारी सुरक्षित की जा रही है, जिससे फसल संबंधी डेटा पूरी तरह प्रमाणिक हो रहा है। जियो-फेंसिंग तकनीक से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे केवल वास्तविक खेत स्थल पर ही किया जाए। सर्वे डेटा का त्रिस्तरीय सत्यापन एआई/एमएल सिस्टम और पटवारी स्तर पर किया जा रहा है। अन्य विभागों द्वारा भी इस डेटा का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। डीसीएस डेटा के आधार पर उपार्जन पंजीयन की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इंटरनेट उपलब्ध न होने की स्थिति में भी सर्वे की विश्वसनीयता बनी रहे। सर्वे के दौरान ली गई फोटो की प्रामाणिकता और सही लोकेशन की पुष्टि प्रणाली द्वारा की जाती है। सर्वे केवल निर्धारित समयावधि में ही संभव है और समय सीमा के बाहर या मोबाइल समय में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होने पर सर्वे स्वतः रुक जाता है। एआई या एमएल एल्गोरिदम के माध्यम से डेटा का क्रॉस-वेरिफिकेशन कर मानवीय त्रुटियों की संभावना को न्यूनतम किया गया है।

फसल क्षेत्र, उत्पादन अनुमान और योजनाओं के क्रियान्वयन में डेटा-ड्रिवन निर्णय लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री को एकीकृत डिजिटल प्रणाली के रूप में विकसित किया गया है। इसमें किसानों की पहचान, भूमि विवरण और योजना संबंधी जानकारी का केंद्रीकृत पंजीकरण एवं सत्यापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में भूमि अभिलेखों का पूर्ण डिजिटल एकीकरण, स्थान आधारित रिकॉर्ड और बहु-स्तरीय डेटा जांच शामिल हैं।

प्रत्येक किसान को 11 अंकीय विशिष्ट डिजिटल पहचान संख्या प्रदान की जा रही है, जिससे एक प्रमाणिक और सटीक किसान डेटाबेस (यूनिफाइड डिजिटल प्रोफाइल) तैयार हो रही है।

कनाडाई प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मुलाकात

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बुधवार देर सांय चंडीगढ़ स्थित उनके आवास संत कबीर कुटीर पर कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी के नेतृत्व में आए उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से भेंट की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच निवेश, नवाचार, शिक्षा, कौशल विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए कहा कि हरियाणा वैश्विक सहयोगों के लिए हमेशा तैयार है, जिससे प्रदेश में कौशल वृद्धि, नवाचार और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने बताया कि हरियाणा के बड़ी संख्या में छात्र कनाडा में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिससे शैक्षणिक सहयोग दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि हरियाणा सरकार द्विपक्षीय सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने वाले सभी विषयों को अपना पूरा समर्थन प्रदान करेगी। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अंतरराष्ट्रीय संबंधों, नवाचार और विदेशी निवेश जैसे क्षेत्रों पर लगातार कार्य कर रहा है।

बैठक के दौरान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान हरियाणा में कनाडा विश्वविद्यालय के परिसर बनाने पर विचार-विमर्श किया गया। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत की स्वदेशी संबंध मंत्री राजन साहनी ने हरियाणा के औद्योगिक विकास, नवाचार और मानव संसाधन विकास से जुड़ी नीतियों की सराहना की।

बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अल्बर्टा के उन्नत कौशल विकास तंत्र और शिक्षा एवं रोजगार के संबंध में चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जिसमें मुख्य रूप से कौशल प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग आधारित कार्यक्रमों में साझेदारी पर भी मंथन हुआ ताकि हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सके।

सरकारी स्कूलों ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मेडिटेशन को अपनाया: हरजोत बैंस

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि मोहाली जिले के सरकारी अपर-प्राइमरी स्कूलों ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बड़ी और नवीन पहल करते हुए रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम की शुरूआत की है।

श्री हरजोत सिंह बैंस और आम आदमी पार्टी पंजाब के प्रभारी श्री मनीष सिसोदिया ने आज मोहाली में एक वर्कशॉप के दौरान स्कूल प्रमुखों और प्रिंसिपलों के साथ विचार-विमर्श किया। शिक्षा मंत्री ने छात्रों की तंदरुस्ती बढ़ाने के उद्देश्य से लागू किए गए रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम के क्रियान्वयन और प्रभावों के बारे में वर्कशॉप में मौजूद लोगों को अवगत करवाया।

श्री बैंस ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में लागू की गई इस पहल के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रमुखों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छात्र अब शांत, एकाग्र और भावनात्मक रूप से मजबूत हो रहे हैं। श्री बैंस ने दोहराया कि राज्य सरकार की योजना है कि ऐसी सकारात्मक पहलें पूरे सूबे में लागू की जाएं। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम (एन.आई.एल.पी.) जैसे शैक्षिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि यह पायलट प्रोजेक्ट 19 जनवरी, 2026 को शुरू किया गया था। इसके तहत रोजाना अभ्यास में सुबह की सभा के बाद 30 मिनट का मेडिटेशन सत्र करवाया जाता है। एकरूपता और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जिले के स्कूलों में साढ़े इक्कीस (21½) मिनट का ध्यान मॉड्यूल प्रसारित और लागू किया गया है।

शिक्षकों से बातचीत करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, सच्ची शिक्षा केवल शैक्षणिक ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि लचीले, भावनात्मक रूप से दृढ़ और एकाग्र व्यक्तियों पर केंद्रित होती है। यह नवीन पहल हमारे छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य में एक सचेत निवेश है। शुरूआती फीडबैक मानसिक स्थिरता में वृद्धि और एकाग्रता को दर्शाता है। यह पंजाब भर में एक अधिक सहायक और सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाने में हमारे विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

यूपी में 06 से 13 फरवरी तक चलेगा 'दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0'

योगी सरकार का दिव्यांगजनों के सेवायोजन के साथ स्व-रोजगार पर भी फोकस, सभी जनपदों में चलेगा एक सप्ताह का विशेष अभियान

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और ठोस पहल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में 06 से 13 फरवरी 2026 तक दिव्यांगजन रोजगार अभियान 2.0 संचालित किया जाएगा। इस विशेष अभियान का उद्देश्य दिव्यांगजनों को सेवायोजन के साथ-साथ स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योगी सरकार की यह पहल दिव्यांगजनों को सम्मानजनक आजीविका, आत्मनिर्भरता और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक और मजबूत कदम है।

प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि अभियान के तहत विगत तीन वर्षों में कौशल विकास मिशन एवं आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षित ऐसे पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़ा जाएगा, जो वर्तमान में जनपदों

में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही जनपद स्तर पर उपलब्ध अन्य इच्छुक दिव्यांगजन भी इस अभियान का लाभ ले सकेंगे।

दिव्यांगजन रोजगार अभियान के दौरान जनपदों में संचालित औद्योगिक इकाइयों एवं अन्य अधिष्ठानों में उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष दिव्यांगजनों का सेवायोजन कराया जाएगा। इसके अलावा एमएसएमई, जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र तथा अन्य विभागों की स्व-रोजगार योजनाओं से भी दिव्यांगजनों को जोड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि हर जनपद में यह अभियान मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा संचालित किया जाएगा, जिसमें जिला उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन केंद्र, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला रोजगार सहायता अधिकारी और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के जिला समन्वयक शामिल होंगे। निर्धारित अवधि में राजकीय आईटीआई को केंद्र बनाकर सेवायोजन एवं स्व-रोजगार संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

सम्पादकीय

ममता बनर्जी का आसमान में सुराख करने का इरादा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक नया इतिहास रच दिया। ममता बनर्जी बाकायदा वकील के तौर पर सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुईं और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में हो रही गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कीं। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब किसी मुख्यमंत्री ने वकील की भूमिका भी निभाई है। सबसे खास बात यह कि ममता बनर्जी अपना या अपनी पार्टी का पक्ष रखने शीर्ष अदालत में प्रस्तुत नहीं हुईं बल्कि उन लाखों कमजोर लोगों का पक्ष रखने के लिए सामने आईं, जो एसआईआर से पीड़ित हैं, जिनके मताधिकार पर सरकारी कार्रवाई का चाबुक चला है। संक्षेप में कहें तो ममता बनर्जी लोकतंत्र को बचाने के लिए मुख्यमंत्री होते हुए भी वकील की भूमिका में आईं। अदालत में अपनी दलीलों को पेश करने के बाद आखिरी में माननीय न्यायाधीशों से उन्होंने यही कहा कि लोकतंत्र बचा लीजिए। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर देश भर में गरीब और कमजोर लोग चिंतित हैं कि उनका नाम कहीं मतदाता सूची से कट न जाए। पांच साल में एक दिन उन्हें मिलता है जब उन्हें उसी कतार में खड़े होने का मौका मिलता है, जिस कतार में समाज का धनाढ्य और प्रभावशाली तबका भी लगता है। वोट देने का अधिकार अमीर और गरीब हरेक के पास एक जैसा है। लेकिन एसआईआर के कारण इस अधिकार पर बड़ी चोट पड़ चुकी है। भाजपा और चुनाव आयोग जिसे धार्मिक शब्दावली की तरह मतदाता सूची का शुद्धिकरण कहते हैं, वह असल में अन्याय और असमानता को बढ़ावा देने वाला है। पिछले साल जून में सबसे पहले बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसका व्यापक और तार्किक विरोध विपक्ष ने किया था। बिहार में इस पर महागठबंधन ने वोटर बचाओ यात्रा भी निकाली थी, जिसे बड़े पैमाने पर समर्थन मिला था। इस मामले में अदालत में याचिकाएं दाखिल हुईं। कायदे से ऐसे में एसआईआर को रोक कर फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए था। लेकिन बिहार में यह पूरी भी हुई और करोड़ों नाम वोटर लिस्ट से कटे, उसके बाद चुनाव हुए और नतीजा सबके सामने है। जिन घुसपैठियों के नाम पर एसआईआर को तत्काल कराने की जरूरत बताई गई, उस पर अब सत्ता पक्ष या चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता कि कितने विदेशी नागरिक बिहार में वोटर लिस्ट में थे। अब घुसपैठियों का यही लचर तर्क प.बंगाल में दिया जा रहा है। यहां तो अर्मत्य सेन जैसे प्रतिष्ठित नागरिक तक को चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया, तो आम गरीब आदमी की बिसात ही क्या है। इसलिए ममता बनर्जी को बुधवार को अदालत में कहना पड़ा कि न्याय बंद दरवाजे के पीछे रो रहा है। बता दें कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष ममता बनर्जी अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम नंबर एक में मौजूद रहीं। मंगलवार को मुख्यमंत्री बनर्जी के नाम पर एक गेट पास जारी किया गया था। मोस्तारी बानू और टीएमसी सांसदों डेरेक ओ 'ब्रायन और डोला सेन की दायर याचिकाओं पर सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच ने सुनवाई की। जिनमें ममता बनर्जी ने अपनी दलील पेश की। सुश्री बनर्जी ने अपनी बात रखने की इजाजत मांगी। उन्होंने कहा, 'सर, मुझे सिर्फ 5 मिनट दें।' सीजेआई ने कहा कि 15 मिनट लीजिए। फिर ममता बनर्जी ने भावुक होकर कहा, 'न्याय बंद कमरों के पीछे रो रहा है। हम कहीं से न्याय नहीं पा रहे। मैंने चुनाव आयोग को 6 बार पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।' ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बंगाल को निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा, 'यह चुनाव आयोग नहीं, व्हाट्सएप कमीशन है। एसआईआर को सिर्फ नाम हटाने का हथियार बनाया जा रहा है, न कि सही जांच का। उन्होंने 24 वर्षों के बाद लागू की गई इस तात्कालिकता पर भी चिंता जताई, जिसे फसल कटाई के मौसम और प्रवासन के चरम समय के दौरान तीन महीनों में जल्दबाजी में पूरा किया गया था, और इसके मानवीय नुकसान को भी दर्ज किया, जिनमें 100 से अधिक मौतें, बीएलओ सदस्यों की मौतें और बड़े पैमाने पर अस्पताल में भर्ती होना शामिल है।

जयंती

खान अब्दुल गफ़्फ़ार खान

जन्म: 6 फरवरी, 1890; मृत्यु: 20 जनवरी, 1988, महान राजनेता थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण "सरहदी गांधी" (सीमान्त गांधी), "बाचा खान" तथा "बादशाह खान" के नाम से पुकारे जाने लगे। 20वीं शताब्दी में पख़्तूनों (या पठान; पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुसलमान जातीय समूह) के सबसे अग्रणी और करिश्माई नेता थे, जो महात्मा गांधी के अनुयायी बन गए और उन्हें 'सीमांत गांधी' कहा जाने लगा। अब्दुल गफ़्फ़ार खाँ का जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही अत्यधिक दृढ़ स्वभाव के व्यक्ति हैं, इसलिये अफगानों ने उन्हें 'बाचा खान' के रूप में पुकारना प्रारम्भ कर दिया। आपका सीमा प्रान्त के कबीलों पर अत्यधिक प्रभाव था। गांधी जी के कट्टर अनुयायी होने के कारण ही उनकी 'सीमांत गांधी' की छवि बनी। विनम्र गफ़्फ़ार ने सदैव स्वयं को एक 'स्वतंत्रता संघर्ष का सैनिक' मात्र कहा, परन्तु उनके प्रसंशकों ने उन्हें 'बादशाह खान' कह कर पुकारा। गांधी जी भी उन्हें ऐसे ही सम्बोधित करते थे। राष्ट्रीय आन्दोलनों में भाग लेकर उन्होंने कई बार जेलों में घोर यातनायें झेली हैं। फिर भी वे अपनी मूल संस्कृति से विमुख नहीं हुए। इसी वजह से वह भारत के प्रति अत्यधिक स्नेह भाव रखते थे।

पुण्यतिथि

मोतीलाल नेहरू

जन्म: 6 मई, 1861–मृत्यु: 6 फरवरी, 1931, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। इनकी पत्नी का नाम 'स्वरूप रानी' था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मोतीलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अपनी ज़िंदगी की शानोशौकत को पूरी तरह से ताक पर रख दिया बल्कि देश के लिए परिजनों सहित अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मोतीलाल नेहरू अपने समय में देश के प्रमुख वकीलों में थे। वह पश्चिमी रहन–सहन, वेषभूषा और विचारों से काफी प्रभावित थे। किंतु बाद में वह जब महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। पंडित मोतीलाल नेहरू अपने समय के शीर्ष वकीलों में थे। उस समय वह हजारों रुपए की फीस लेते थे। उनके मुवक्किलों में अधिकतर बड़े जमींदार और स्थानीय रजवाड़ों के वारिस होते थे, किंतु वह गरीबों की मदद करने में पीछे नहीं रहते थे।

कल मिलेंगे

पति (फोन पर पत्नी से)–तुम बहुत प्यारी हो...!
पत्नी–थैंक्स...!
पति–तुम बिल्कुल राजकुमारी जैसी हो...!
पत्नी–थैंक्यू सो मच... और बताओ क्या कर रहे हो
पति–खाली बैठा था, सोचा मजाक ही कर लूं...!
पत्नी आओ बेलन लेकर इंतजार कर रही हूं

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी। **मुद्रक**-देवानंद राय।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635
E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: मोदी नेतृत्व की वैश्विक दृढ़ता

-ललित गर्ग

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते उस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत को आगे बढ़ने से रोक पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्यापारिक समझौता भारत की परिपक्व कूटनीति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के परिदृश्य में कोई भी समझौता केवल आंकड़ों या कर-प्रतिशतों तक सीमित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, नेतृत्व की दृढ़ता और भविष्य की दिशा का भी संकेतक होता है। भारत और अमेरिका के बीच हालिया व्यापारिक सहमति, जिसके अंतर्गत प्रस्तावित 50 प्रतिशत टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है, इसी दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी घटना है। यह निर्णय केवल आर्थिक राहत नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक शक्ति-संतुलन और भारत की बढ़ती सौदेबाजी क्षमता का प्रमाण है। यहां देर आए, दुरुस्त आए की कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। जब अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर ऊँचे टैरिफ का दबाव बनाया गया था, तब यह आशंका व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था को अंततः झुकना पड़ेगा। वैश्विक व्यापार का हालिया इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि बड़ी शक्तियां अक्सर दबाव की राजनीति के माध्यम से अपने हित साधती हैं। किंतु फरवरी 2025 में आरंभ हुई इस व्यापारिक प्रक्रिया का फरवरी 2026 में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना यह दशार्ता है कि भारत ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता किया। भारत ने समय लिया, परिस्थितियों का मूल्यांकन किया और अंततः संतुलित व सम्मानजनक परिणाम प्राप्त किया।

50 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक की टैरिफ कटौती का तात्कालिक प्रभाव व्यापारिक जगत और शेयर बाजार में दिखाई दिया। निवेशकों का भरोसा लौटा, निर्यातकों को राहत मिली और बाजार में सकारात्मक संकेत उभरे। किंतु इस निर्णय का वास्तविक महत्व इससे कहीं अधिक व्यापक है। यह इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अब केवल नियमों का पालन करने वाला देश नहीं, बल्कि नियमों के निर्माण और पुनर्परिभाषा में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने वाला राष्ट्र बन चुका है। अमेरिका जैसी महाशक्ति का अपने रुख में नरमी लाना भारत की आर्थिक ताकत, रणनीतिक धैर्य और राजनीतिक आत्मविश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि उसमें संवाद है, पर दबाव के आगे समर्पण नहीं। चाहे वह रक्षा सहयोग हो, ऊर्जा सुरक्षा हो या व्यापारिक समझौते-हर क्षेत्र में भारत ने अपने हितों को केंद्र में रखते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस व्यापारिक डील में भी भारत ने बिना झुके, बिना रुके और बिना कमजोर पड़े अपनी शर्तें स्पष्ट रूप से रखीं। यही कारण है कि अंततः अमेरिका को अपने प्रस्तावों में संशोधन करना पड़ा। यह केवल एक व्यापारिक जीत नहीं, बल्कि राजनीतिक परिपक्वता और नेतृत्व की दृढ़ता का उदाहरण है। इस समझौते से भारतीय उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में एक उन्नत स्थिति प्राप्त होगी। कम टैरिफ का अर्थ है कि भारतीय उत्पाद अमेरिकी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी होंगे, उनकी पहुंच बढ़ेगी और मेक इन इंडिया को नया प्रोत्साहन मिलेगा। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, कृषि-आधारित उत्पाद और उभरते तकनीकी क्षेत्र-सभी को इससे दीर्घकालिक लाभ होने की संभावना है। भारत अब केवल सस्ता श्रम या कच्चा माल उपलब्ध कराने वाला देश नहीं, बल्कि मूल्यवर्धित उत्पादन और नवाचार की दिशा में अग्रसर अर्थव्यवस्था बनता जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसदीय दल की बैठक में जिस संयम और आत्मविश्वास के साथ भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को निरंतर धैर्य का परिणाम बताया, वह उनकी कूटनीतिक शैली का सार है। यह समझौता किसी अचानक हुए घटनाक्रम का नतीजा नहीं, बल्कि एक वर्ष तक चली रणनीतिक प्रतीक्षा, विकल्पों के विस्तार और संतुलित संवाद का परिणाम है। मोदी ने स्पष्ट संकेत दिया कि सरकार ने विपक्ष की आलोचनाओं और तात्कालिक दबावों के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वैश्विक व्यापार और भू-राजनीति में जल्दबाजी अक्सर महंगी पड़ती है। अमेरिका का झुकना किसी भावनात्मक मित्रता का परिणाम नहीं, बल्कि ठोस रणनीतिक विवशता का नतीजा है। बीते एक वर्ष में भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास विकल्प हैं-रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी बढ़ती भूमिका।

यदि वाशिंगटन भारत पर एकतरफा दबाव बनाए रखता, तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं। ट्रंप द्वारा 500 अरब डॉलर के आयात, शून्य टैरिफ और रूसी तेल त्यागने जैसे नाटकीय दावे इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा थे, जिन्हें भारत ने न तो सार्वजनिक टकराव का मुद्दा बनाया और न ही स्वीकारोक्ति दी। मोदी का इन पर मौन यह दशार्ता है कि भारत इस घटनाक्रम को अंतिम समझौते के रूप में नहीं, बल्कि दिशा-निर्धारण के रूप में देख रहा है। इसके विपरीत, भारतीय विपक्ष इस पूरे प्रकरण में अपनी राजनीतिक अधीरता और रणनीतिक अपरिपक्वता को उजागर करता रहा। उसने टैरिफ को लेकर तात्कालिक लाभ-हानि की भाषा में सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाताएं समय, धैर्य और बहुस्तरीय गणनाओं की मांग करती हैं। विपक्ष यह समझने में असफल रहा कि कूटनीति में कभी-कभी पीछे हटना नहीं, बल्कि प्रतीक्षा करना ही सबसे बड़ा कदम होता है। आज जब अमेरिका को अपना अड़ियल रुख छोड़ना पड़ा है और भारत फिर से वैश्विक प्रतिस्पर्धा की अग्रिम पंक्ति में खड़ा दिख रहा है, तब यह स्पष्ट है कि मोदी की नीति न केवल दबाव से मुक्त थी, बल्कि दूरदर्शी भी। यही नीति भारत को एक आत्मविश्वासी, प्रभावशाली और सौदे की शर्तें तय करने वाली शक्ति के रूप में स्थापित कर रही है।

इस पूरे घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि यह वैश्विक व्यापार में दबाव आधारित राजनीति के अंत का संकेत देता है। लंबे समय से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं टैरिफ, प्रतिबंध और नीतिगत दबावों के माध्यम से छोटे या उभरते देशों को अपनी शर्तें मानने के लिए विवश करती रही हैं। भारत ने इस प्रवृत्ति को न केवल चुनौती दी, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि आत्मविश्वास, आर्थिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बल पर किसी भी दबाव को संतुलित संवाद में बदला जा सकता है। भारत-अमेरिका संबंधों के संदर्भ में यह समझौता एक नए राजनीतिक आभामंडल के निर्माण का भी संकेत देता है। यह संबंध अब केवल रणनीतिक या सामरिक सहयोग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक साझेदारी के एक नए स्तर की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रभाव केवल इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक राजनीति में बहुध्रुवीय व्यवस्था को और अधिक मजबूती देगा। दुनिया धीरे-धीरे यह स्वीकार कर रही है कि भविष्य का नेतृत्व किसी एक शक्ति के हाथ में नहीं, बल्कि संतुलित साझेदारियों के माध्यम से उभरेगा, और भारत उसमें एक केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

इस व्यापारिक प्रगति से मोदी सरकार की अंतरराष्ट्रीय साख में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह साख किसी प्रचार या दावे पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित है। भारत आज विश्व मंच पर एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है, जो अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक स्थिरता और सहयोग में भी सकारात्मक भूमिका निभाता है। यही संतुलन उसे अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग पहचान देता है। महाशक्ति बनने की भारत की यात्रा भावनात्मक नारों पर नहीं, बल्कि आर्थिक आंकड़ों, रणनीतिक समझौतों और वैश्विक स्वीकार्यता पर आधारित है।

दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और इस प्रकार के व्यापारिक समझौते उस यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। यह स्पष्ट होता जा रहा है कि भारत को आगे बढ़ने से रोक पाना अब किसी के लिए आसान नहीं है। निश्चित तौर पर यह व्यापारिक समझौता भारत की परिपक्व कूटनीति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार की दुनिया में कोई भी निर्णय केवल आर्थिक गणित नहीं होता, वह राष्ट्र की संप्रभुता, आत्मसम्मान और नेतृत्व की परिपक्वता का भी प्रमाण होता है। देर से लिया गया सही निर्णय, जल्दबाजी में किए गए गलत समझौतों से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। भारत ने धैर्य रखा, आत्मसम्मान बनाए रखा और अंततः अपने हितों के अनुरूप परिणाम हासिल किया। निश्चित ही नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत न केवल सुरक्षित है, बल्कि आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है और यह विश्वास ही उसे महाशक्ति बनने की उड़ान देता है।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सत्ता की निष्कंटक राह बरास्ते सुनेत्रा की ताजपोशी

-उमेश चतुर्वेदी

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे

राजनीति जज्बात से नहीं, हालात के हिसाब से चलती है। महाराष्ट्र में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण इसका उदाहरण है। सुनेत्रा के आंसू अभी सूखे भी नहीं, पति अजित पवार के निधन के शोक से उबरना तो दूर की बात है। फिर भी उन्होंने सियासी तकाजे को ही प्राथमिकता दी और महाराष्ट्र की पहली महिला उपमुख्यमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। पारिवारिक वज्रपात के बीच सिंहासन पर बैठने को लेकर उनकी आलोचना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज के सोचने का अपना ढंग है। सियासी हस्तियों से भी उसे सामाजिक परंपराओं और पारिवारिक संस्कारों को अपनाने की उम्मीद रहती है। सुनेत्रा सामाजिक सवालों से बच नहीं सकतीं। लेकिन सवाल यह है कि सुनेत्रा की ताजपोशी से महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है? प्रश्न यह भी उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि सुनेत्रा ने आनन-फानन में शपथ ले ली। महाराष्ट्र के राजभवन में जनवरी महीने के आखिरी दिन जो राजनीतिक इतिहास रचा गया, उसकी कहानी किसने लिखी थी।

महाराष्ट्र में भले ही शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली हो, लेकिन राज्य की राजनीति के सबसे मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार हैं। यह बात छुपी हुई नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों धड़ों के बीच सुलह और एकीकरण की बात चल रही थी। शरद पवार तो खुलकर स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनकी ओर से जयंत पाटिल, अजित पवार से बात कर रहे थे। कहा तो यहां तक जा रहा है कि 12 फरवरी को दोनो पार्टियों के विलय पर अजित और शरद में सहमति हो चुकी थी। लेकिन अजित के न रहने के बाद समीकरण बदल गए। अजित के साथ गए अहम नेताओं प्रफुल्ल पटेल, आर आर पाटिल और सुनील तटकरे जैसे नेताओं की आशंकाएं बढ़ गईं। उन्हें डर था कि अगर विलय हुआ तो शरद पवार की पार्टी पर नियंत्रण बढ़ जाएगा। इसके चलते सुप्रिया सुले की पार्टी पर पकड़ बढ़ जाएगी। सुप्रिया के नियंत्रण में इन नेताओं का काम करना असहज होता। प्रफुल्ल कभी शरद पवार के बेहद नजदीकी होते थे। अजित के साथ जाकर एक तरह से उन्होंने शरद पवार के साथ दगाबाजी ही की है। उन्हें ज्यादा आशंका थी कि विलय के बाद पार्टी पर पकड़ होने के चलते शरद के बहाने सुप्रिया का चाबुक उन पर चल सकता है। लेकिन अगर पार्टी अलग रहती है और सुनेत्रा के हाथ कमान रहती है तो इन नेताओं की सियासी सेहत बनी और बची रह सकती है। यही वजह है कि अजित के निधन के चलते हुए आधिकारिक शोक की मियाद खत्म होते ही प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जैसे नेता सक्रिय हो गए। विधायक दल की बैठक बुलाई गई और सुनेत्रा को तत्काल उसका नेता चुनकर उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार कर लिया गया। शरद पवार भले ही इस सियासी पटकथा का लेखक सुनील तटकरे और प्रफुल्ल पटेल को मानते हों, लेकिन महाराष्ट्र के सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि असल में यह पटकथा राज्य की बीजेपी ने लिखा है। पटेल और तटकरे जैसे नेताओं ने सिर्फ इसे अमल में लाने में भूमिका निभाई है।

सवाल उठ सकता है कि अगर सुनेत्रा शपथ नहीं लेतीं तो क्या बीजेपी की सियासी सेहत गड़बड़ा सकती थी, क्योंकि राज्य में बीजेपी के 132 और एकनाथ शिंदे की अगुआई वाली शिवसेना के 57 विधायक हैं। राज्य में बहुमत के लिए महज 145 सीटें चाहिए होती हैं। इस लिहाज से देखें तो बीजेपी की अगुआई वाली सरकार को कोई खतरा नहीं होने जा रहा था। अजित समेत एनसीपी के 41 विधायक पिछले चुनाव में चुने गए हैं। अजित के न रहने पर यह संख्या 40 रह गई है। लेकिन बीजेपी की चिंता दूसरी है। शरद पवार की राजनीतिक स्थिति भले ही ठीक ना हो, लेकिन जैसे ही दोनों एनसीपी का विलय होता, शरद ताकतवर होकर उभरते। महाराष्ट्र का यह चाणक्य एक बार फिर स्थापित होता और बीजेपी के लिए नई सिरदर्दी खड़ी हो जाती। शरद पवार इतने प्रभावी और सियासी रूप से तिकड़मी हैं कि बीजेपी के लिए संकट बनकर उभर जाते। उनकी प्रभावी सक्रियता के चलते शिवसेना के गुटों को भी एक करने की वे कोशिश कर सकते थे। भले ही यह सोच कल्पना लग रही हो, लेकिन एकबारगी स्वीकार कर लें कि ऐसा होता तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसी होती। महाराष्ट्र में जिला परिषदों के चुनाव हो रहे हैं। पहले विधानसभा और बाद में स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस की अगुआई वाली महाविकास अघाड़ी को सफलता नहीं मिली। अजित पवार के न रहने के चलते कांग्रेस को सक्रिय होना चाहिए था।

अजित की अगुआई वाले जिला परिषद उम्मीदवार उनके न रहने की वजह से थोड़े आशंकित और निराश भी हैं। इस निराशा को कांग्रेस भुना सकती थी। वह एनसीपी के उम्मीदवारों पर डोरे डाल सकती थी और अपने उम्मीदवारों को नए जोश से भर सकती थी। अजित बेशक सत्ता में थे, लेकिन उन्हें विपक्षी खेमे के लिए अब भी हसरतभरी निगाह से ताकतवर नेता के रूप में देखा जा रहा था। अजित के न रहने के बाद विपक्षी नेतृत्व के लिए आसमान खुल गया है। शरद पवार की उम्र हो गई है। शरद के बाहर जाने के बाद से ही कांग्रेस राज्य में कमजोर हुई है। सुप्रिया सुले का नेतृत्व ऐसा नहीं है कि वह राज्यव्यापी प्रभाव हासिल कर पाए। यह माहौल कांग्रेस के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकता है। ऐसे माहौल में कांग्रेस को अपने ताकतवर नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर आगे लाना चाहिए था। लेकिन वह ऐसा करती नहीं दिख रही। 2014 के बाद से उसने जिस नैरेटिव युद्ध की शैली को अपनाया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसी युद्ध प्रक्रिया को जारी रखे हुए है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास फुर्सत नहीं है कि वह महाराष्ट्र या किसी अन्य राज्य की राजनीति के बारे में स्थानीय जरूरतों के लिहाज से सोचे और स्थानीय समुदायों के लिए उन्हीं के बीच से प्रभावी नेतृत्व उभारे।

रणनीतिक लिहाज से देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी सभी दलों पर एक बार फिर बीस पड़ती नजर आ रही है। उसने सुनेत्रा को अपने खेमे में लाकर एक तीर से दो निशाने साध लिए हैं। उसने एनसीपी की ओर निश्चिंतता हासिल कर ली है, शरद पवार को एक बार फिर किनारे रखने में सफल हुई है और अपने लिए खतरा बनने की शरद की संभावनाओं को एक तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है।

महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई देश की आर्थिक राजधानी भी है। इसी वजह से केंद्रीय सत्ता के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली महाराष्ट्र की सत्ता मानी जाती है। माना जाता है कि कारपोरेट और औद्योगिक जगत पर सबसे ज्यादा पकड़ महाराष्ट्र के सिंहासन की होती है। मौजूदा राजनीति में आर्थिकी सबसे ज्यादा प्रभावी है। महाराष्ट्र की सत्ता पर पकड़ देश की आर्थिक ताकतों की नब्ज पर पकड़ बनाती है। यह बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी अपनी इस पकड़ को कमजोर होते नहीं देखना चाहती।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तम्भकार हैं
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

खेल/विदेश/कारोबार

डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर मॉस्को का दोटूक जवाब-'हमारे भारतीय मित्र कभी नहीं बदलेंगे'

(एजेन्सी)।

रूस ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उसे विश्वास नहीं है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूसी तेल का साथ छोड़ेगा। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया था कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत नई दिल्ली रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा। मारिया जखारोवा ने बुधवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका द्वारा स्वतंत्र देशों को यह बताना कि उन्हें किसके साथ व्यापार करना चाहिए, कोई नई बात नहीं है।

2 फरवरी को, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच महीनों से चल रही बातचीत पर सस्पेंस खत्म हो गया। ट्रंप ने कहा कि इस डील के तहत भारतीय आयात पर आपसी टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया जाएगा और यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के साथ भारत के तेल व्यापार को रोकने पर सहमत हो गए हैं। भारत ने बाद में टैरिफ में कटौती की पुष्टि की, लेकिन भारत-रूस ऊर्जा संबंधों के भविष्य पर ट्रंप के दूसरे दावे को स्वीकार नहीं किया।

ट्रंप के दावों के कुछ दिनों बाद, रूस की जखारोवा ने कहा कि ट्रंप यह "तानाशाही" करने की कोशिश कर रहे थे कि एक स्वतंत्र देश को क्या करना चाहिए और मॉस्को को विश्वास नहीं था कि उसके "भारतीय दोस्तों" ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों पर अपना रुख बदल लिया है।

जखारोवा ने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति का यह तय करने की कोशिश करना कि भारत जैसा स्वतंत्र देश किसके साथ व्यापार कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। रूस के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि हमारे भारतीय दोस्तों ने अपना रुख बदल लिया है," उन्होंने आगे कहा कि संसाधनों का व्यापार भारत और रूस दोनों के लिए फायदेमंद था।

समाचार एजेंसी पीटीआई के हवाले से उन्होंने कहा, "हमें पूरा विश्वास है कि भारत द्वारा रूसी हाइड्रोकार्बन की खरीद दोनों देशों के लिए फायदेमंद है और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने में योगदान देती है। हम भारत में अपने भागीदारों के साथ इस क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग जारी रखने के लिए तैयार हैं।"

जहां जखारोवा ने विश्वास जताया कि ट्रंप के तेल के दावे के बाद भारत अपनी ऊर्जा व्यापार नीतियों में बदलाव नहीं करेगा, वहीं रूस के प्रेस सचिव दिमित्री पेसकोव ने एक अलग राय पेश करते हुए कहा कि भारत किसी भी देश से तेल खरीदने के लिए स्वतंत्र है। पीटीआई के अनुसार, दिमित्री पेसकोव ने कहा, "हम, अन्य सभी अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा विशेषज्ञों के साथ, अच्छी तरह से जानते हैं कि रूस भारत को तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का एकमात्र आपूर्तिकर्ता नहीं है। भारत ने हमेशा इन उत्पादों को अन्य देशों से खरीदा है। इसलिए, हमें इसमें कुछ भी नया नहीं दिखता है।"

रूस के साथ भारत का तेल व्यापार नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच आर्थिक तनाव का एक बड़ा मुद्दा था। पिछले साल, ट्रंप ने इस तेल व्यापार का हवाला देते हुए भारत पर टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया था। इस महीने भारत के साथ एक ट्रेड डील की घोषणा करते हुए, ट्रंप ने जोर देकर कहा कि भारत मॉस्को के साथ एनर्जी ट्रेड बंद करने पर सहमत हो गया है, एक ऐसा कदम जिससे उनके अनुसार यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी।

4–5 दिन में भारत–अमेरिका व्यापार समझौता पर होगा साइन–गोयल

(एजेन्सी)।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण पर संयुक्त बयान को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने की संभावना 4-5 दिनों में है। संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद, अमेरिका भारत पर टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत करने का कार्यकारी आदेश जारी करेगा। वर्तमान में, भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ और रूसी कच्चे तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगता है।

गोयल ने पत्रकारों को बताया कि समझौते के पहले चरण के लिए कानूनी समझौते पर मार्च के मध्य तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि संयुक्त बयान के बाद एक विस्तृत कानूनी समझौता किया जाएगा। गोयल ने यह भी कहा कि इस समझौते में निवेश की कोई प्रतिबद्धता नहीं है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि बयान पर हस्ताक्षर होने के बाद यह एक कानूनी समझौता बन जाएगा और मार्च के मध्य तक इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम कर देगा। इससे पहले, पिछले साल फरवरी में हुई एक बैठक में ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद ऋतु तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने पर सहमति जताई थी। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कई दौर की बातचीत हुई, लेकिन ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद व्यापार समझौते पर प्रगति रुक गई। इसमें रूस से कच्चे तेल की खरीद पर लगाया गया 25 प्रतिशत दंडात्मक टैरिफ भी शामिल था।

मोदी-ट्रंप की फोन पर बातचीत उसी दिन हुई जब विदेश मंत्री एस जयशंकर वाशिंगटन डीसी की यात्रा पर थे। अधिकारियों ने बताया कि अब भारत का टैरिफ प्रतिस्पर्धी निर्यात अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। उन्होंने इंडोनेशिया पर 19 प्रतिशत, वियतनाम पर 20 प्रतिशत, बांग्लादेश पर 20 प्रतिशत और चीन पर 34 प्रतिशत अमेरिकी टैरिफ का उदाहरण दिया।

पिछले सप्ताह आधिकारिक सूत्रों ने कहा था कि भारत और अमेरिका ने व्यापार समझौते के लिए बातचीत में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति की है।

वीरेंद्र सहवाग को भारतीय टीम पर भरोसा, इतिहास रचने की उम्मीद

(एजेन्सी)।

टी20 क्रिकेट अब वैसा नहीं रहा, जैसा 2007 में था, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर सबको चौंका दिया था। उस दौर में 160झ170 का स्कोर बचाव योग्य माना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ खेल की रफ्तार भी बदली है और अब 250 से ज्यादा रन भी सुरक्षित नहीं माने जाते हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, युवा बल्लेबाजों की आक्रामक सोच, बड़े शॉट्स पर लगातार काम और बल्लेबाजों के अनुकूल हालात ने टी20 को पूरी तरह बदल दिया है।

गौरतलब है कि अब 200 से ऊपर के स्कोर आम बात हो चुके हैं, जब तक पिच या मौसम बल्लेबाजों के खिलाफ न हो। ऐसे में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाला आगामी टी20 वर्ल्ड कप बल्लेबाजों का टूर्नामेंट साबित हो सकता है। इसी कड़ी में भारत के पूर्व विस्फोटक ओपनर वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम इतिहास रचने की पूरी क्षमता रखती है।

सहवाग ने कहा कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है और हालिया 4-1 से न्यूजीलैंड पर मिली सीरीज जीत इसका उदाहरण है। उन्होंने बताया कि टीम में युवा जोश और अनुभवी खिलाड़ियों का संतुलन दिखाई देता है, जो बड़े टूर्नामेंट में बेहद अहम होता है। बता दें कि सहवाग ने युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी तेज शुरूआत भारत को विरोधियों पर शुरूआती दबाव बनाने में मदद करती है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने करियर में किया करते थे। मौजूद जानकारी के अनुसार,

ईशान किशन की हालिया शतकीय पारी और वरुण चक्रवर्ती की सटीक गेंदबाजी भी टीम की ताकत को और बढ़ाती है। सहवाग का मानना है कि निचले क्रम में रिंकू सिंह और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं, खासकर तब जब शीर्ष क्रम जल्दी आउट हो जाए।

गौरतलब है कि अब तक कोई भी टीम घरेलू जमीन पर टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है, लेकिन सहवाग को भरोसा है कि जैसे भारत ने 2011 में घर पर वनडे वर्ल्ड कप जीता था, वैसे ही यह टीम टी20 में भी इतिहास बना सकती है। उन्होंने यहां तक कहा कि यह भारतीय टीम 2007 की विश्व विजेता टीम से भी अधिक संतुलित और मजबूत है, जिसमें बेहतरीन बल्लेबाज, उपयोगी ऑलराउंडर, गुणवत्ता वाले स्पिनर और तेज गेंदबाज मौजूद हैं।

आखिर में सहवाग ने खिलाड़ियों को सलाह दी कि वर्ल्ड कप के दौरान मीडिया और सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, ताकि बाहरी दबाव से दूर रहकर अपने खेल पर पूरा ध्यान दे सकें और नतीजे अपने पक्ष में ला सकें हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के प्रसारण के बाद मुख्यमंत्री करेंगे बच्चों से संवाद

कैथल के आरकेएसडी कॉलेज में होगा कार्यक्रम

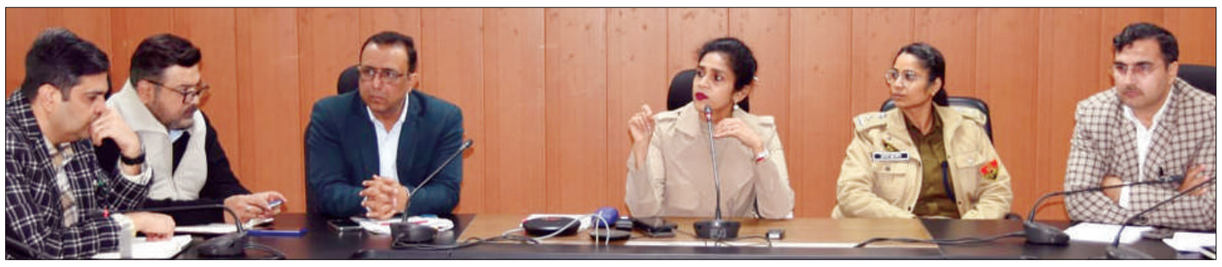

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि शुक्रवार छह फरवरी को शिक्षा निदेशालय द्वारा आरकेएसडी कॉलेज कैथल में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी बच्चों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण प्रदेश के सभी जिलों में दिखाया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन पूरी गंभीरता और निष्ठा के साथ करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

डीसी अपराजिता ने वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहीं थीं। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में सुबह 10 बजे आयोजित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा विभाग, बिजली विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग और स्वास्थ्य विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति और जन स्वास्थ्य विभाग को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को आपातकालीन स्थिति के लिए मेडिकल टीमें तैनात रखने को कहा गया है। इसी प्रकार उन्होंने पुलिस विभाग को कॉलेज परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

डीसी अपराजिता ने कहा कि यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह इस मंच के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को सफलता के मंत्र देंगे। सभी विभाग एक टीम की तरह काम करें ताकि यह संवाद प्रेरणादायक सिद्ध हो।

शिक्षा विभाग का भी यही लक्ष्य है कि बोर्ड परीक्षाओं से ठीक पहले विद्यार्थियों के मन से परीक्षा का डर निकालकर उनमें आत्मविश्वास भरा जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करेंगे।

इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, जिला परिषद के सीईओ सुरेश रावश, आरटीए गिरीश कुमार, एचएसवीपी के ईओ वकील अहमद, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष, डीआरओ चंद्रमोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

ऑनलाइन नीति के विरोध में HSEB कर्मचारी पंचकूला रवाना, ज्ञापन सौंपा

राज्य प्रधान इकबाल चन्दना के आह्वान पर राजौंद सब यूनिट के कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी महासंघ की सब यूनिट राजौंद के कर्मचारियों ने वीरवार, 5 फरवरी को राज्य प्रधान इकबाल चन्दना के आह्वान पर ऑनलाइन गलत नीति के विरोध में जोरदार कदम उठाया। कर्मचारियों ने अतिरिक्त मुख्य सचिव (पावर) पंचकूला को ज्ञापन सौंपने के लिए राजौंद से पंचकूला की ओर प्रस्थान किया।

सब यूनिट राजौंद के प्रधान अश्विनी ढांडा ने बताया कि मैनेजमेंट द्वारा लागू की गई ऑनलाइन नीति कर्मचारी विरोधी है और इससे कर्मचारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जब तक प्रबंधन यह ऑनलाइन नीति वापस नहीं लेता, तब तक कर्मचारियों का विरोध लगातार जारी रहेगा।

अश्विनी ढांडा ने आगे बताया कि सेक्टर काउंसिल द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जा रही है, जिसमें बड़े आंदोलन और हड़ताल जैसे कड़े कदम भी शामिल हो सकते हैं। यदि हड़ताल का आह्वान किया जाता है तो राजौंद के सभी कर्मचारी बढ़-चढ़कर उसमें भाग लेंगे। इस मौके पर महासंघ के कई पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे, जिनमें मुकेश सचिव, परवीन उप प्रधान, कुलदीप बनवाला, सुखदेव, रोहतास, रमन, जगबीर, होशियार (लिपिक), कृष्ण जखोली, जगबीर, दीपक जुलानी, मनजीत, लाला राजौंद तथा राजेंद्र राजौंद सहित अनेक कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वे एकजुट हैं और किसी भी कर्मचारी विरोधी नीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

खानपुर प्रखंड मुख्यालय के सभागार में भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान 2.0 का लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित

संजना भारती संवाददाता
अर्जुन कुमार झा

समस्तीपुर। खानपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित सभागार में गुरुवार को भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 का लॉन्चिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला योजना पदाधिकारी निशांत कुमार पटेल ने दीप प्रज्वलित कर इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 28 जनवरी से 14 अप्रैल 2026 तक मिशन मोड में 6 सूचकांकों पर कार्य किया जाऐगा। जिसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि पशुपालन और शिक्षा विभाग संबंधित सूचकांक शामिल हैं।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को मिथिला परंपरा अनुसार सम्मानित किया गया।पिरामल फाउंडेशन के केशव कुमार ने विकास कार्यों और संपूर्णता अभियान 2.0 की कार्य योजना का प्रेजेंटेशन दिया।

जिला योजना पदाधिकारी ने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं की सत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करना है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि अभियान की अवधि में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण,पशु स्वास्थ्य सहित सभी प्राथमिक क्षेत्रों में सत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जाए। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया और किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड का वितरण किया गया। इसके अलावा, विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर विजय कुमार चंद्रा ने कहा कि आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत खानपुर प्रखंड में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए प्रखंड अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधि, जीविका, सभी विभागों के समन्वय, सक्रिय सहभागिता हेतु धन्यवाद दिए एवं प्रेरित किए। सभी छह सूचकांक को 100% सैचुरेट करने हेतु सभी के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से शपथ लिया गया। कार्यक्रम में सभी विभागों के द्वारा स्टॉल के माध्यम से दिए जा रहे सेवाओं का प्रदर्शनी लगाया गया जिसका निरीक्षण उपस्थित सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में खानपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया और गुब्बारे के माध्यम से संपूर्णता अभियान 2.0 का संदेश दिया गया।

इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिनमें जिला योजना पदाधिकारी निशांत कुमार पटेल, सहायक योजना पदाधिकारी प्रशांत कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी खानपुर विजय कुमार चंद्र, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ राणा नितेश सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वर्षा सिन्हा, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी संजीव कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा कार्यालय से लाल बाबू, कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी खानपुर, प्रखंड उप प्रमुख अमरेंद्र कुमार राय, पीरामल फाउंडेशन टीम, समस्तीपुर, प्रखंड के पंचायत से आये मुखिया अरुण कुमार सिंह कुशवाहा, रविन्द्र कुमार प्रसाद, संजीव कुमार सिंह, चंदेश्वर राय, आंगनबाड़ी सेविका, स्वास्थ्य कर्मी एवं प्रखंड अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित थे।

आरोही मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल सोंगरी में सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण का आयोजन

सूर्य नमस्कार अभियान में 371 विद्यार्थियों ने लिया भाग

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। हरियाणा योग आयोग एवं आयुष विभाग द्वारा 12 जनवरी से 12 फरवरी तक चलाए जा रहे सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत आरोही मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल, गांव सोंगरी में सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. शकुंतला दहिया के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम के दौरान आयुष योग सहायक संदीप कुमार व रीना ने विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया और इसके लाभों की जानकारी दी। विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉ. सुनीता आहूजा ने बताया कि स्कूल में समय-समय पर योग से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास सुनिश्चित किया जा सके।

प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि सूर्य नमस्कार 12 आसनों का एक समूह है, जिसमें प्रणामासन, हस्तउत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार और भुजंगासन प्रमुख हैं। इनमें से कुछ आसनों को दो बार दोहराया जाता है। इन आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, शरीर मजबूत बनता है और ऊर्जा का संचार होता है।

इस सूर्य नमस्कार प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 371 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। डॉ. शकुंतला दहिया ने बताया कि 12 जनवरी से प्रारंभ हुआ यह सूर्य नमस्कार अभियान 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती के अवसर पर संपन्न किया जाएगा।

उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित

संजना भारती बदायूं ब्यूरो प्रमुख
इंतजार हुसैन

बिल्सी। गुरुवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक बिल्सी नगर के सिटी कॉम्प्लेक्स, तहसील रोड पर आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई तथा संगठनात्मक विस्तार पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इस अवसर पर प्रदेश युवा अध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोंटू के संतुति पर प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल ने बिल्सी क्षेत्र के कर्मठ एवं सक्रिय व्यापारी नेता अवधेश लड्डा महेश्वरी को युवा प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी दी। उनके मनोनयन से व्यापारियों में हर्ष की लहर दौड़ गई। उपस्थित व्यापारियों द्वारा उन्हें पटका पहनाकर सम्मानित किया गया।

बैठक में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोन्टू ने नव मनोनीत पदाधिकारियों को पटका एवं मनोनयन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जिस गर्मजोशी एवं एकजुटता के साथ बिल्सी इकाई का विस्तार हुआ है, आने वाले समय में यह इकाई संगठन के लिए मील का पत्थर साबित होगी शीघ्र ही सदस्यता अभियान चलाकर व्यापारियों को संगठन से जोड़ा जाएगा

नवमनोनीत जिला उपाध्यक्ष मृगांक कुमार उर्फ टीटू जैन ने कहा कि व्यापारी समाज अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेगा तथा संघर्ष के मार्ग से समाधान निकालने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। नव मनोनीत युवा प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष अवधेश लड्डा ने कहा कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने हेतु नगर बिल्सी में एक भव्य व्यापारी सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें तहसील स्तर तक के व्यापारियों की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।

वहीं नवमनोनीत तहसील अध्यक्ष अजीत गुप्ता ने कहा कि संगठन के अंतिम पायदान तक के व्यापारियों को जोड़ा जाएगा तथा तहसील बिल्सी का सघन दौरा कर रिक्त इकाइयों का गठन शीघ्र किया जाएगा। नगर अध्यक्ष सचिन असावा ने बताया कि संगठन के माध्यम से नगर की प्रमुख समस्याओं को शासन एवं प्रशासन स्तर तक पहुँचाकर उनके समाधान का प्रयास किया जाएगा।

अंत में बैठक में जिलाध्यक्ष नवनीत गुप्ता शोन्टू ने जिला कार्यालय से हुए जारी मनोनयन पत्र युवा वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष अवधेश लड्डा, जिला उपाध्यक्ष मृगांक कुमार टीटू जैन, जिला चेयरमैन चंद्रसैन महेश्वरी, जिला युवा मंत्री निशिकांत महेश्वरी, जिला युवा अध्यक्ष विवेक चौहान, तहसील अध्यक्ष अजीत गुप्ता, तहसील महामंत्री आशीष जैन, तहसील संगठन मंत्री डॉ. विक्की, कोषाध्यक्ष संतोष गुप्ता, नगर अध्यक्ष सचिन असावा, नगर महामंत्री धीरज, उपाध्यक्ष एवं नगर कोषाध्यक्ष प्रमोद जैन, युवा नगर अध्यक्ष विशाल वार्ष्णेय, युवा महामंत्री नीरज शर्मा, युवा कोषाध्यक्ष जाहिद हुसैन एवं नगर संगठन मंत्री रवि वार्ष्णेय को पटका पहनाकर सम्मानित कर प्रेषित किया।

बैठक में दर्जनों व्यापारियों की उपस्थिति रही तथा नवगठित इकाई एवं व्यापारी टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

श्री गुरु रविदास महाराज जी के उपदेश के अनुसार समानता वाले समाज की रचना के लिए पंजाब सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री मान

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार श्री गुरु रविदास महाराज जी द्वारा दिए गए उपदेशों पर चलते हुए समानता वाले समाज की रचना के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु जी की महान विरासत को बनाए रखने के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा 6 फरवरी को होशियापुर जिले में स्थित खुरालगढ़ में राज्य स्तरीय समागम आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकाश पर्व के अवसर पर पूरी कैबिनेट संगत के साथ श्री गुरु रविदास जी को श्रद्धा और सम्मान अर्पित करने के लिए नतमस्तक होगी।

भगवंत सिंह मान ने समस्त संगत से इस राज्य स्तरीय समागम में पूरे धार्मिक उत्साह और बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने लोगों से समाज में प्रचलित विभिन्न सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए श्री गुरु रविदास जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा कि श्री गुरु रविदास जी की बाणी समस्त मानवता के लिए प्रकाश-स्तंभ है और उन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का रास्ता दिखाया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस दिव्य बाणी से समाज को विभिन्न समस्याओं से मुक्त किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले ही खुरालगढ़ में लगभग 148 करोड़ रुपये की लागत से विश्व स्तरीय यादगार बना चुकी है, जो राज्य सरकार द्वारा श्री गुरु रविदास जी को विनम्र श्रद्धांजलि है। उन्होंने कहा कि यह यादगार सुविधाओं से लैस इमारत, मल्टीलेवल पार्किंग, मीनार-ए-बेगमपुरा, संगत हॉल, अत्याधुनिक ऑडिटोरियम और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि श्री गुरु रविदास जी ने समस्त मानवता की भलाई, समाज के सभी वर्गों की समानता का संदेश दिया और इस प्रकार समानतावादी मूल्यों पर आधारित समाज की रचना की।

प्राथमिकता के साथ किया जाए जन शिकायतों का निदान: डीसी अपराजिता

समाधान शिविर में डीसी अपराजिता ने सुनी आमजन की शिकायतें

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का निदान प्राथमिकता के साथ किया जाए। किसी भी रूप से शिकायत को लंबित नहीं रखा जाए। सभी अधिकारी अपने विभाग से संबंधित शिकायतों को गंभीरता के साथ लें और उनका स्थाई समाधान निकाले। शिकायत के समाधान की अपडेट रिपोर्ट समाधान प्रकोष्ठ के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। डीसी अपराजिता वीरवार को लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में फरियादियों को शिकायत सुनने के दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहीं थीं। उन्होंने कहा कि आमजन की संतुष्टि बेहद जरूरी है, ऐसे में समाधान शिविर के माध्यम से आमजन की शिकायत का समाधान तत्परता से करते हुए लोगों को राहत पहुंचाएं। समाधान शिविर में आई शिकायतों को कोई भी विभाग के अधिकारी लंबित न रखते हुए निवारण करवाएं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दिशा-निर्देशानुसार नागरिकों की शिकायतों का समाधान एक ही स्थान पर और एक ही छत के नीचे करने के उद्देश्य से सप्ताह में दो दिन सोमवार व गुरुवार को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक जिला स्तर एवं उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों की मॉनिटरिंग करते है और समय-समय पर समीक्षा बैठक करते हैं। सभी आमजन अपनी व्यक्तिगत एवं जनहित की शिकायतों का निदान पाने के लिए लिखित शिकायत दें और उसके साथ संबंधित दस्तावेज जरूर लगाएं।

इस अवसर पर एसपी उपासना, एडीसी सुशील कुमार, जिला परिषद के सीईओ सुरेश रावश, आरटीए गिरीश कुमार, एचएसवीपी के ईओ वकील अहमद, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष, डीआओ चंद्रमोहन सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

गोपीचौक ओवर हेड टैंक की जलापूर्ति आज रहेगी बाधित

एसबी संवाददाता

बदायूं। नगर पालिका के जलकल विभाग द्वारा नागरिकों को सूचित किया है कि कबूलपुरा, घंटाघर, गोपी चौक, अल्फा खां सराय, पक्का बाग, चौधरी सराय और लालपुल आदि क्षेत्र में स्थित ओवरहेड टैंक की पेयजलापूर्ति बाधित रहेगी।

जलकल अभियन्ता जल नितिन सक्सेना ने बताया कि भूसा मंडी स्थित नये नलकूप की पाइप लाइन को ओवरहेड टैंक से जोड़ने का यह कार्य शुक्रवार को कराया जाएगा। इस आवश्यक रखरखाव कार्य के चलते सायंकाल और सुबह के समय क्षेत्र की जलापूर्ति प्रभावित रहने की संभावना है। नगर पालिका ने क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे असुविधा से बचने के लिए आवश्यक एहतियात बरतें। विभाग ने अनुरोध किया है कि जलापूर्ति प्रभावित होने को ध्यान में रखते हुए उसी दिन प्रातःकाल प्राप्त होने वाली जलापूर्ति से अपनी आवश्यकता के अनुसार पेयजल का भंडारण कर लें। इससे शाम के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नल जल योजना ठप: पानी के लिए परेशान है लोग

एसबी संवाददाता

मंसूरचक (बेगूसराय)। बहरामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 6 में नलजल योजना से पानी सप्लाई विगत कुछ दिनों से बंद रहने को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि स्थानीय मुखिया को शिकायत किया गया लेकिन ठिकेदार कि मनमानी चल रहा है महीने में तीन चार दिन ठीक रहता है फिर वही हालत हो जाता है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि नल जल योजना से पानी सप्लाई विगत 15 दिनों से बंद है। जिससे लोगों को स्वच्छ जल पीने को नहीं मिल रहा है।

आक्रोशित ग्रामीणों में संतोष राय, नीरज राय, राम किशुन राय, गणेश राय, महेश्वर राय, उर्मिला देवी, सिकंदर रजक, समेत दर्जनों लोगों ने जिला पदाधिकारी से नल जल योजना का सुचारू रूप से संचालित करने की मांग की है।

वर्षा मदान के निधन पर सामाजिक संगठनों व राजनीतिक दलों के नेताओं ने जताया शोक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/विजय गर्ग

असंध। समाजसेवी सतीश मदान की पत्नी स्वर्गीय वर्षा मदान के निधन से पूरे समाज में शोक की लहर है। वर्षा मदान एक सप्ताह से बीमार चल रही थी। लंबी बीमारी के चलते अमृतसर में उनका देहांत हो गया था। उनके अंतिम संस्कार में कई सामाजिक लोगों ने भाग लेकर उनके परिवार को सांत्वना दी। वही उनके निधन पर पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों व पत्रकारों ने गहरा दुख व्यक्त किया है। सभी ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की एवं उनके परिजनों का ढाढस बंधाया।

सूरजकुंड मेले में दिखा दक्षिण भारत की चित्रकला का वैभव

एसबी संवाददाता/चण्डीगढ़। फरीदाबाद की सुरम्य अरावली पहाड़ियों में आयोजित 39वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला कला प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मेले में देश-विदेश की विविध संस्कृतियों के बीच दक्षिण भारत की पारंपरिक चित्रकला अपनी अमिट छाप छोड़ रही है। तमिलनाडु से आए शिल्पकार केशव की तंजौर पेंटिंग पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शिल्पकार केशव के स्टॉल पर 12 हजार रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की बेशकीमती पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई हैं।

मेंटेनेंस को लेकर 4 घंटे तक बिजली आपूर्ति रहेगी बाधित

एसबी ब्यूरो

मंसूरचक(बेगूसराय)। 33 केवी लाइन बछवाडा. से भरौल तक मरम्मति कार्य होना है। जिसको लेकर पेड़ पौधों की कटाई एवं तारों को दुरुस्त किया जाएगा। जिसके कारण 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक विधुत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त बातें कि जानकारी कनीय विधुत अभियंता हर्ष कुमार मौर्य ने दिया। उन्होंने बताया कि पीएसएस भरौल की सभी विधुत आपूर्ति बाधित रहेगी।

ताजमहल

भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिह्न...

आगरा का ताजमहल भारत की शान और प्रेम का प्रतीक चिह्न माना जाता है। उत्तरप्रदेश का तीसरा बड़ा जिला आगरा ऐतिहासिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मुगलों का सबसे पसंदीदा शहर होने के कारण ही उन्होंने दिल्ली से पहले आगरा को अपनी राजधानी बनाया।

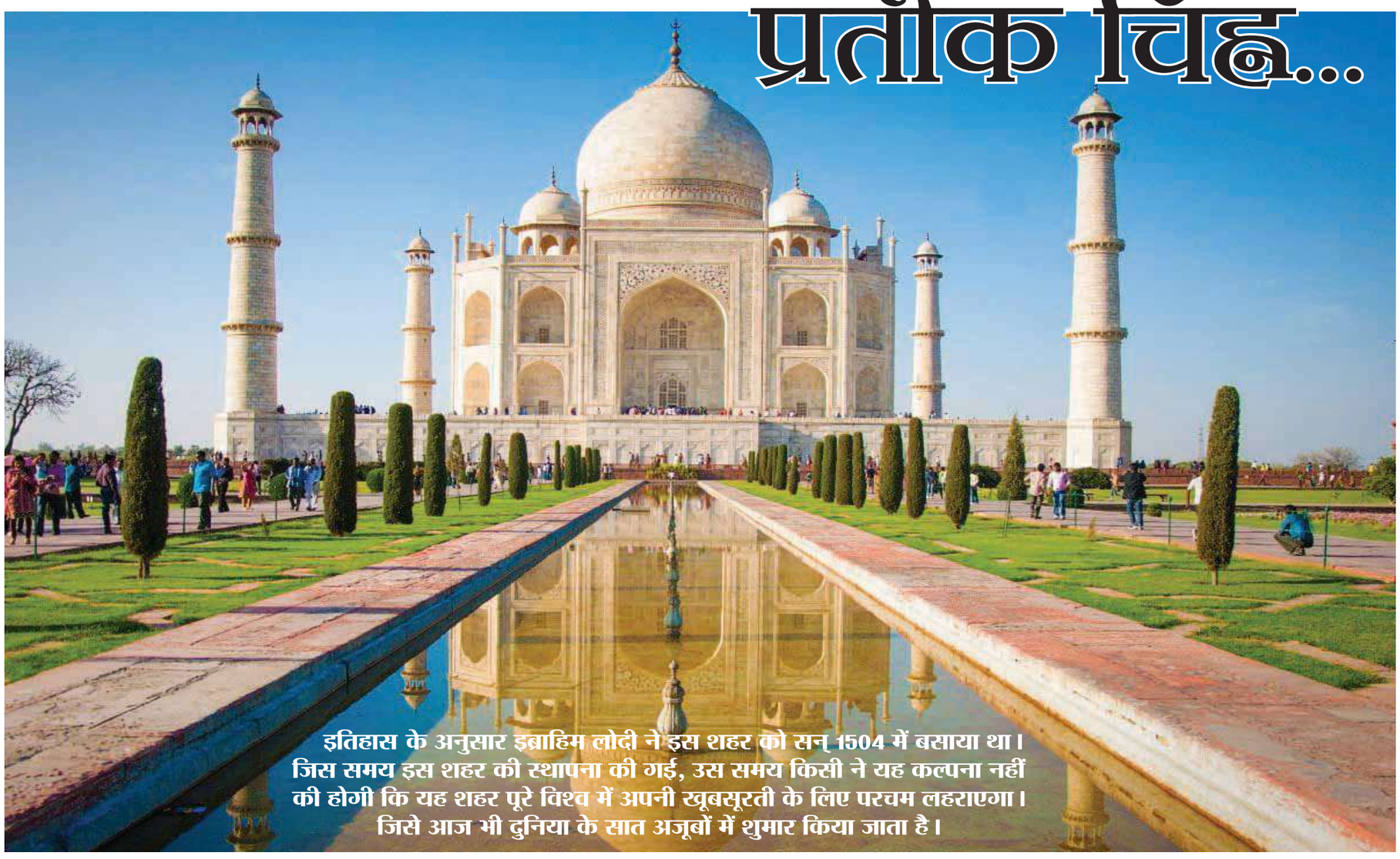

इतिहास के अनुसार इब्राहिम लोदी ने इस शहर को सन् 1504 में बसाया था। जिस समय इस शहर की स्थापना की गई, उस समय किसी ने यह कल्पना नहीं की होगी कि यह शहर पूरे विश्व में अपनी खूबसूरती के लिए परचम लहराएगा। जिसे आज भी दुनिया के सात अजूबों में शुमार किया जाता है।

स्थापत्य कला की जीती-जागती तस्वीर आगरा शहर दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसे बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। इसी तरह बुखारा शहर, जो मध्य एशिया में स्थित हैं, वहां से जिस कारीगर को बुलवाया गया वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। विराट कद के गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तम्बुल में रहने वाले दक्ष कारीगर बुलाया गया तथा मिनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया। इस प्रकार ताजमहल के निर्माण से पूर्व छः महीनों में कुशल कारीगरों को तराश कर उनमें से 37 दक्ष कारीगर इकट्ठे किए गए, जिनके देखरेख में बीस हजार मजदूरों के साथ कार्य किया गया। इसी प्रकार ताज निर्माण में लगाई गई सामग्री संगमरमर पत्थर राजस्थान के मकराणा से, अन्य कई प्रकार के कीमती पत्थर एवं रत्न बगदाद, अफगानिस्तान, तिब्बत, इजिप्त, रूस, ईरान आदि कई देशों से इकट्ठा कर उन्हें भारी कीमतों पर खरीद कर ताजमहल का निर्माण करवाया गया। ई.1630 में शुरू हुआ इसका निर्माण कार्य करीब 22 वर्षों में पूर्ण हुआ, जिसमें लगभग बीस हजार मजदूरों का योगदान माना जाता है। इसका मुख्य गुंबद 60 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है।

इतिहास :

मुगल बादशाह की मुहब्बत और शिद्दत का परिणाम ही है, 'ताजमहल' जिसे खूबसूरती का नायाब हीरा कहा जाता है। गुंबदनुमा इस इमारत को जब आप सिर उठाकर ऊपर देखते हैं तो इसकी नक्काशीदार छतें और दीवारें किसी आश्चर्य से कम नहीं लगतीं।

इसका यह इतिहास तो बच्चे-बड़े सभी की जुबान पर है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी दूसरी पत्नी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर 'ताजमहल' न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहां आते हैं। दूधिया चांदनी में नहा रहे ताजमहल की खूबसूरती को निहारने के बाद आप कितनी भी उपमाएं दें, वह सारी फीकी लगती हैं।

आगरा में ताजमहल के अलावा भी कई चीजें देखने लायक हैं : जैसे...

◆ आगरा फोर्ट (रेड फोर्ट)-

आगरा फोर्ट यहां के महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। इसका निर्माण ई. 1565 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया था। स्थापत्य कला का यह बेजोड़ नमूना लाल पत्थरों से निर्मित हैं। इसमें जहांगीर महल (दीवाने-ए-खास) भी बना है, जो खूबसूरत शीशमहल के रूप में प्रचलित है।

◆ फतेहपुर सीकरी-

आगरा से लगभग 35 किलोमीटर दूर स्थित इस स्थान को अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, जो स्थापत्य की बेजोड़ कलाओं से परिपूर्ण है।

◆ मेहताब बाग-

यमुना नदी की विपरीत दिशा में 'ताजमहल' के पास ही बना हुआ है मेहताब बाग। कई तरह के फूलों और अनेक पेड़-पौधों से सुसज्जित होने के कारण विदेशी सैलानियों को काफी लुभाता है।

◆ रामबाग-

_रामबाग को बाबर ने 1528 ई. में बनवाया था। यह ताजमहल के उत्तरी भाग में ढाई किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसे मुगलों द्वारा निर्मित सबसे पुराने बागों में से एक माना जाता है।

◆ जामा मस्जिद-

शाहजहां की बेटी जहांआरा बेगम की याद में सन् 1648 ई. में बनाई गई थी यह जामा मस्जिद।

बड़ी ही खूबसूरती से इसके गुंबद भी तराशे गए हैं। इतने वर्षों बाद भी इसकी खूबसूरती जस-की-तस बनी हुई है।

मुमताज महल और शाहजहां की कब्र ताजमहल के निचले हिस्से में आमने-सामने बनी हुई है।

आज भी आगरा शहर देशी-विदेशी सैलानियों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है।

पर्यटन विभाग की ओर से प्रतिवर्ष 'ताज महोत्सव' का आयोजन किया जाता है।

खूबसूरत स्थापत्य कला में निर्मित होने की वजह यहां गर्मी हो या ठंड, हर मौसम में पर्यटकों की भीड़ देखी जा सकती है।

कोणार्क के सूर्य मंदिर में उपलब्ध होंगी विश्वस्तरीय पर्यटक सुविधाएं

ओडिशा की स्थापना के दिन- उत्कल दिवस के साथ ही आज कोणार्क के सूर्य मंदिर में आगंतुकों के लिए एक विश्वस्तरीय अनुवाद केंद्र और पर्यटक सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। सुविधाओं का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सूर्य मंदिर ओडिशा का गौरव है और यह जरूरी है कि विश्व को वास्तुशिल्प के इस अजूबे के बारे में जानकारी हो और इस दिशा में अनुवाद केंद्र एक कदम है।

इस मौके पर एक जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रधान ने आगंतुकों के अनुकूल अवसंरचना और सुविधाएं विकसित करने के लिए इंडियन ऑयल फाउंडेशन की तारीफ की। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर की मूर्तिकला संबंधी समृद्धि को फिर से जीवंत बनाने के लिए उन्होंने प्रख्यात वास्तुकार रघुनाथ महापात्रा की भी प्रशंसा की।

उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में विकसित की गई आधुनिक सुविधाएं भविष्य में ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को आकर्षित करेगी।

भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है कौसानी, नेचर लवर्स इन जगहों को मिस न करें

सीढ़ीदार पहाड़ी धान के खेतों और हरे-भरे ऊंचे-ऊंचे देवदार के घने जंगलों के बीचों बीच रुद्रधारी फॉल्स कमाल की खूबसूरती संजोए है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड है कौसानी, नेचर लवर्स इन जगहों को मिस न करेंभारत में ऐसी कई जगह हैं, जो खूबसूरती में किसी विदेश की जगह से कम नहीं है। ऐसी ही एक जगह है कौसानी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में 6075 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर बसा है खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी। दिलकश नजारों के चलते ही इस जगह को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है।

कहीं-कहीं इसे कुमाऊं का स्वर्ग भी कहते हैं। कौसानी पहुंचकर आपको हिमालय की चोटियों का 350 किलोमीटर फैला नजारा एक ही जगह से देखने का मौका मिलता है।

लीची के बगीचे से घिरा खूबसूरत शहर है तेजपुर

पूर्वोत्तर भारत की नायाब सुंदरता में 'तेज' भरता है असम स्थित तेजपुर। कभी 'मोहब्बत का शहर' तो अक्सर देश के 'सबसे उपयुक्त रहने लायक' शहरों में इसका नाम लिया जाता है। क्या है खास इस शहर में? जानते हैं उमेश पंत के साथ तेजपुर के इस खास सफर में..

गुवाहाटी से तकरीबन 180 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तेजपुर। कल-कल बहती और अपनी मौज में लहराती विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर बसे इस शहर को असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। मंदिरों, घाटों और हजारों साल पुरानी स्थापत्य कला के अवशेषों के लिए मशहूर यह शहर असम का पांचवां सबसे बड़ा शहर है।

तेजपुर असम का वह छोर है, जिसके आगे से अरुणाचल प्रदेश आरंभ हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों की तलहटी पर बसा यह शहर अपनी भौगोलिक बसावट के कारण सामरिक दृष्टि से भी खासी अहमियत रखता है। इतना ही नहीं, यह शहर 'सिटी ऑफ रोमांस' के नाम से भी मशहूर है यानी यह है मोहब्बत का शहर भी।

जब खाली करना पड़ा पूरा शहर

वह 1962 के भारत-चीन युद्ध का दौर था और नवंबर का महीना था, जब भारत की सेना को कामेंग सेक्टर से पीछे हटना पड़ा था। कामेंग सेक्टर अब अरुणाचल प्रदेश में है पर तब इसे नॉर्थ-ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी (नेफा) के नाम से जाना जाता था। भारत के पीछे हटने की खबर से नजदीकी शहर तेजपुर में यह बात फैल गयी कि चीन की सेना कभी भी यहां तक पहुंच सकती है। इस खबर से पूरा शहर दहशत में आ गया। जान-माल के नुकसान से बचने के लिए एहतियातन पूरे शहर को खाली करवा दिया गया। हजारों लोग बैलगाड़ियों में सामान लादकर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जमा होने लगे, ताकि स्टीमर की मदद से नदी पार करके सुरक्षित ठिकानों तक पहुंच सकें। तेजपुर में वरिष्ठ पर्यटन ऑफिसर बासब बोरा बताते हैं, 'मुझे वह दौर याद है। मैंने अपनी आंखों से वह दहशत देखी थी। तब कालिया भोमोरा पुल नहीं बना था। लोगों को फेरी से नदी पार करनी पड़ती थी। उस वक्त सभी लोग जान बचाने के लिए असम के ऊपरी इलाकों की तरफ भाग रहे थे।' बोरा के मुताबिक, लोग शहर छोड़ने से पहले अपनी धन-संपत्ति को बचाने के लिए उसे शहर के बीचों-बीच बनी झील में डाल दिया। कुछ लोग जो शहर में सुरक्षित बचे रह गए, लड़ाई खत्म हो जाने के बाद वे इस धन-संपत्ति की बदौलत मालामाल हो गए।

सांस्कृतिक धरोहरों का ठिकाना

असम की तीन मशहूर सांस्कृतिक हस्तियां तेजपुर की ही देन हैं। ज्योति प्रसाद अग्रवाल, बिष्णु प्रसाद राभा और भूपेन हजारिका। बिष्णु राभा असम के संगीत जगत का एक बड़ा नाम हैं और भूपेन हजारिका को देश में कौन नहीं जानता। 'आमी एक जाजाबर' और 'दिल हूम-हूम कर' जैसे मशहूर गीत लिखने और गाने वाले भूपेन हजारिका का बचपन यहीं बीता था।

भूपेन हजारिका की याद में यहां 'भूपेन हजारिका कला भूमि' नाम से एक ओपन एयर थिएटर भी बना है। यहां भूपेन हजारिका की एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई है। ज्योति प्रसाद अग्रवाल भी असम के संगीत और साहित्य जगत में एक जाना-माना नाम हैं। उन्होंने 1935 में असम के सिनेमा जगत की पहली फिल्म 'जौयमती' बनाई थी। शहर के बीचों-बीच बने उनके पुरखों के घर 'पोकी' को अब एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है।

मनोरम है पदुम पोखरी झील

पदुम पोखरी नाम की खूबसूरत झील भी यहां है जिस पर एक खूबसूरत टापू बना है। इस टापू को अब एक पार्क में तब्दील कर दिया गया है। पदुम यानी कमल और पोखरी यानी तालाब। कुछ लोग इसे 'कमल तालाब' भी कहते हैं। इसके अलावा, शहर के बीचों-बीच 'बोर पोखरी' नाम का एक तालाब भी है। कहा जाता है कि ये दोनों जुड़वा तालाब यहां के बाण राजा और उनकी बेटी उषा की स्मृति-चिह्न हैं। पदुम पोखरी में लोहे का एक पुल इस टापू से जमीन के मुख्य भाग को जोड़ता है। और हां, यदि आप यहां आएं तो झील के किनारे टॉय ट्रेन की यात्रा और पैडलिंग का भी आनंद लेना न भूलें। यह झील बच्चों के लिए आम आकर्षण है। यहां द्वीप पर एक म्यूजिकल फाउंटेन भी है। यहां बजने वाले संगीत और चलने वाली ठंडी हवाओं के कारण यहां का वातावरण मनोरम हो जाता है। स्थानीय भाषा में पदुम पुखुरी तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। यह स्थल राज्य परिवहन बस स्टेशन के बहुत करीब है।

खास है इस लीची की मिठास

अगर आपने तेजपुर की लीची नहीं चखी, तो क्या चखा! अपने अलग आकार और गहरे लाल रंग की वजह से अलग से पहचान में आने वाली इस लीची को मुंह में डालते ही इसकी मिठास जीभ में घुल जाती है। तेजपुर के पोरोवा गांव में 'लीची पुखुरी' नामक जगह पर पैदा होने वाली इस लीची की देश ही नहीं, विदेश में भी मांग है। तेजपुर की लीची को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन (जीआई) टैग भी मिल चुका है। इस टैग के मिलने के बाद किसी भी उत्पाद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल जाती है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उस उत्पाद को उसी जगह पर उगाया जाए, जहां वह मूल रूप से पैदा होता है।